

2-4-19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित तथा वकील रेस्पोजेन्ट सं० 9 लगा० 12 उपस्थित। उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील ही उनकी बहस है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा पटवार हल्का अखैपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित ख०नं० 658 रकबा 0.5285 हे० बरानी अव्वल, ख०नं० 683/737 रकबा 0.35 हे० एवं ख०नं० 684/738 रकबा 0.1300 हे० कुल कित 3 कुल रकबा 1.0085 हे० स्थित है। वादग्रस्त भूमि में से प्रत्येक अपीलान्ट का 1/20 हिस्सा खातेदारी है, रेस्पोजेन्ट सं० 1 लगा० 8 की पृथक-पृथक रूप से 1/20-1/20 हक हिस्सा खातेदारी है। अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट सं० 2 लगा० 8 के पिता प्रभात ने बिना किसी अधिकारिता के अपने 1/20 हिस्से की भूमि के अतिरिक्त अपीलान्ट्स एवं रेस्पोजेन्ट्स सं० 2 लगा० 8 के हिस्से की 9/20 भूमि का बैचान रेस्पोजेन्ट सं० 9 लगा० 12 के हक में पृथक-पृथक रूप से कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण सं० 236 अपने हित में खुलवा लिया जिससे विवश होकर अपीलान्ट्स ने एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा माननीय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के यह वाद सं० 70/2018 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के रेस्पोजेन्ट सं० 1 लगा० 8 एवं रेस्पोजेन्ट सं० 10 के खिलाफ दायर किया गया है। रेस्पोजेन्ट सं० 9 लगा० 12

पत्रावली
पेश
की
9/5
97/5/19

अतिरिक्त कसब
जयपुर

(चतुर्थ)

द्वारा अपीलान्ट के कब्जे काश्त का अवरोध उत्पन्न करने पर रेस्पोंडेन्ट सं० 1 से इस बाबत उलाहना दिये जाने पर उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट सं० 9 लगा० 12 के पक्ष में खुलने की जानकारी दी जिस पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट्स को दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से अपीलान्ट्स को जानकारी हुई। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में देरी जानबूझकर नहीं की गई है बल्कि परिस्थितिवश हुई है जो क्षम्य योग्य है। अतः अपीलान्ट्स को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र सावधि मानी जावें।

अप्रार्थी सं० 9 लगा० 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्तों द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट को वाकैयात तथ्यों की पूर्व से पूर्ण जानकारी रही है। वरवक्त पंजीकृत विलेख में गवाह बतौर उनके भ्राता के हस्ताक्षर रहे हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त करना एवं जानकारी का श्रोत नकल प्राप्त होने के पश्चात् मिथ्या दर्ज किया है। जबकि अपीलान्ट ने अपील मीमो के प्रारंभ में ही नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष पेश करना स्वीकार किया है। उक्त वाद दिनांक 09.07.2018 को पेश किया गया था। अतः प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.08.2018 को जानकारी होने का कथन करना मिथ्या है। नामान्तरकरण सं० 236 दिनांक 17.05.2016 की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारंभ से ही रही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मियाद मिथ्या दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा दायर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसमें देरी होने का कोई समुचित कारण दर्ज नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद तोषी झूठे तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे। वकील रेस्पोंड द्वारा दौराने बहस निम्न न्यायिक दृष्टान्तों को भी प्रस्तुत किया:-

1. आर.आर.डी 1995 पेज सं० 120
2. आर.आर.टी. 2017 पेज सं० 944

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील पुत्रों द्वारा अपने जीवित पिता सहित उनके भाईयों तथा उनके द्वारा उनके कब्जे काश्त की भूमि को विक्रय की जाने पर पेश की गई है।

अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित किया गया है कि उनको रेस्पोंडेन्ट सं० 9 लगा० 12 द्वारा अपीलान्ट के कब्जे काश्त का अवरोध उत्पन्न करने पर रेस्पोंडेन्ट सं० 1 से


अंतरगत
कलकत्ता
जबपुर

इस बाबत उलाहना दिये जाने पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट सं० 9 लगा० 12 के पक्ष में खुलने की जानकारी दी, जिस पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट्स को दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त होने से अपीलान्ट्स को जानकारी हुई, जबकि उनके द्वारा अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलान्ट्स ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के यहां वाद सं० 70/2018 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पोंडेन्ट सं० 1 लगा० 8 एवं रेस्पोंडेन्ट सं० 10 के खिलाफ दायर किया गया है। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 14.08.2018 को नियत थी। अर्थात् उक्त तिथि से पूर्व अपीलान्ट द्वारा दावा पेश किया जा चुका था। रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता का भी यही कथन है कि अपीलान्ट को तथ्यों की पूर्व से पूर्ण जानकारी रही है। पंजीकृत विलेख में भी गवाह बतौर उनके भ्राता के हस्ताक्षर रहे हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष उक्त वाद दिनांक 09.07.2018 को ही पेश कर दिया गया था। अर्थात् अपीलान्ट को दिनांक 06.08.2018 को जानकारी होने का कथन करना मिथ्या है।

अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में इस तथ्य की जानकारी नहीं दी है कि उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में वाद कब किस तिथि को प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा तथ्य को छुपाते हुए कपटपूर्वक यह कथन किया है कि तारीख पेशी दिनांक 14.08.2018 को नियत है जिससे इस बात को बल मिलता है कि अपीलान्ट द्वारा तथ्य की जानकारा होने को उनके द्वारा छुपाया जा रहा है।

चूंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.08.2018 से पूर्व ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में दावा पेश किया जा चुका था परन्तु अपीलान्ट्स द्वारा अपील में मिथ्या कथन किया है कि उसे दिनांक 06.08.2018 से पूर्व नामा० की जानकारी नहीं थी। जबकि उसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर में दिनांक 06.08.2018 से पूर्व ही वाद पेश कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा मियाद बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले अस्वीकार है।

अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सुनाया गया।


(डॉ. अशोक कुमार)

जयपुर